नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी मनीष कुमार ने आइआइएम में विशिष्ट लेक्चर सीरीज में कहा-

जर्मन डुअल वीटीई सिस्टम से बढ़ाएंगे यूथ की स्किल

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

इंदौर. आइआइएम इंदौर ने विदेश मामलों के मंत्रालय के सहयोग से शनिवार को विशिष्ट लेक्चर सीरीज आयोजित की, जिसमें पूर्व भारतीय राजदूत और गेटवे हाउस की निदेशक नीलम देव मुख्य स्पीकर रहीं। इसके अलावा भारत के आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्री, इनोवेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विषय पर एक इंडस्ट्री मीट भी हुई। इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिलास्तर पर रोजगार पैदा करने और युवाओं को स्किल बनाने के प्रयास होंगे। इसके तहत स्थानीय स्तर पर जॉब्स की क्या कंडीशन,

कितने जॉब पैदा हो सकते हैं, युवाओं को किस तरह के कौशल से रोजगार मिल सकता है। इस हिसाब से काम होगा। उन्होंने कहा, सरकार का ज्यादा फ़ोकस युवाओं के स्किल्स सुधारने में है। इसलिए जर्मन डुअल वीटीई सिस्टम को लाने की तैयार कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री और आइटीआई साथ में कोर्स चलाएंगे। फिलहाल देश में 11 हजार आइटीआइ हैं।

ट्रेनिंग के बाद 50 फीसदी युवाओं को मिला रोजगार : उन्होंने बताया, 2017-18 में सभी मंत्रालयों की स्किल योजनाओं के तहत 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जा चुका हैं। जबिक पीएम कौशल विकास योजना में 20 लाख युवाओं की स्किलिंग हुई है। ट्रेनिंग पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50 फीसदी को जॉब मिली हैं।

स्कूल, कॉलेज लेवल से ही ट्रेनिंग की तैयारी : पीएम कौशल विकास योजना अब कॉलेज व स्कूली संस्थानों के साथ चलाई जाएगी। कॉलेज लेवल पर ही ब्लॉक चैन, रोबोटिक्स, सायरबर सिक्युरिटी जैसे कोर्स पढ़ाएंगे, जिससे रोजगार मिलने से अच्छी संभावना हैं। कई कॉलेजेस खुद को स्किल विवि में बदलने के लिए सपर्क में हैं।

अमरीका में किसानों को सब्सिडी से किसी को आपत्ति नहीं : देव

पूर्व एंबेसडर नीलम देव ने ग्लोबल वर्ल्ड में हो रही उथल-पुथल से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब विश्व संस्थाएं बनी तो हम यूके के अधीन थे। इकोनॉमी छोटी थी इसलिए कभी हमारे हितों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब हम ब्रिस्क, शंघाई कॉरपोरेशन सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सदस्य बन गए हैं। अब हम वैश्विक नीतियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। अमरीका ट्रेड वॉर का टारगेट चीन है। इसका भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा। हमें यूरोपियन प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इन स्थितियों में

फायदा उठाने का मौका बनाना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में सिर्फ भारत के पीडीएस सिस्टम को कोसा जाता है, जबिक अमरीका और यूरोपियन देश भी अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। इसलिए हमें भी ऐसी संस्थानों में सदस्य बनकर प्रभाव डालना जरूरी हैं। मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ानी होगी, तभी हम नीतियां बदलने में भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने बताया, 2016 में हुई तीन घटनाओं ने दुनिया में नया दौर शुरू कर दिया है। पहला अमरीका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का चुनाव, यूरोप से ब्रिटेन का अलग होना और चीन द्वारा साउथ चाइना सी को लेकर इंटरनेशन ट्रिब्यूनल के दिए फैसले को नकारने से वैश्विक व्यवस्था बदली है।

Patrika, (City Live) July 8, 2018 Page-18

भारत में आशंका बनी रहती है काम होगा या नहीं

शार्प इंडिया लिमिटेड के पूर्व एमडी इस्गोई ने कहा- बुलेट ट्रेन के 2023 में भी चल पाने पर संदेह

इंदौर। नईदुनिया रिपोर्टर

भारत में जापान से भारी मात्रा में निवेश की संभावना है खासतौर पर कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, लेकिन भारत के बारे में जो एक धारणा बन गई है वह यह है कि यहां समय पर काम नहीं हो पाता। इसलिए यह आशंका बनी रहती है कि काम होगा भी या नहीं। उदाहरण के लिए बुलेट ट्रेन जिसे 2022 तक होना था अब 2023 में हो पाएगा यह भी संदेह से देखा जा रहा है। यह बात शार्प इंडिया लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर टोमियो इस्गोई ने आईआईएम इंदौर में आयोजित इंडस्ट्री मीट में कही।

आईआईएम इंदौर में इंडस्ट्री मीट में विशेषज्ञों ने रखे विचार

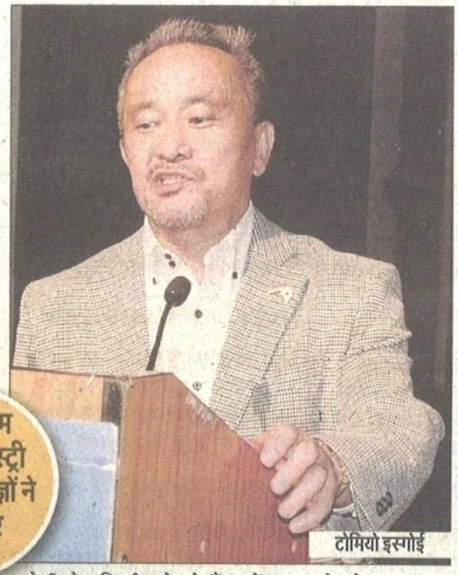

टोमियो इस्गोई

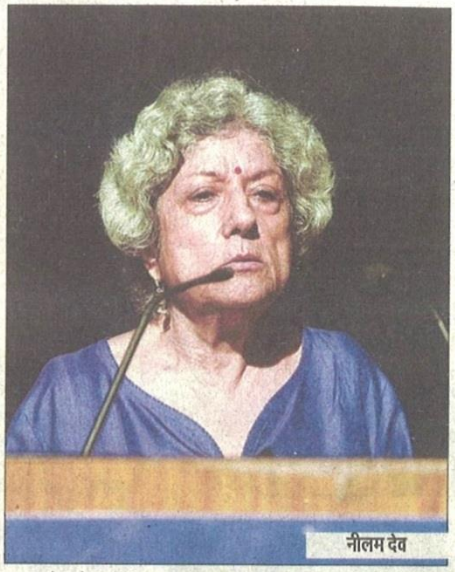

नीलम देव

उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत में प्रोडक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना भी जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रखना जरुरी है। निवेश आकर्षित करने के लिए भारत की सरकार को ईको सिस्टम को पूरी तरह से सुविधाजनक बनाना होगा। क्लीयर प्लान लाना होंगे और उन्हे समय सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि जापान सोर्टिंग, सिस्टेमाइजिंग, शाइनिंग और सेल्फ डिसिप्लीन के मॉडल पर काम करता है। इस साल की इंडस्ट्री मीट की थीम 3ईज इंडस्ट्री, इन्नोवेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज ईकोनोमिक ग्रोथ थी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष कुमार ने कहा कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। हमें इन परिवर्तनों के हिसाब से स्वयं को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और आगे आने वाले सालों में यह और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में ही स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में स्किल यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। 2017-18 में 20 लाख लोगों की स्किलिंग की जा चुकी है, जिनमें से 50 फीसदी को जॉब मिल गया है। कुमार ने कहा मध्यप्रदेश में विकास की बहुत क्षमताएं हैं और जॉब भी काफी हैं लेकिन लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते। हम आईटीआई और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी मिले। इस हेतु स्किल डुएल ट्रेनिंग के जर्मन वीटीआई मॉडल पर काम कर रहे हैं। जापान के साथ हम टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहे हैं। जिसके पहले बैच में तमिलनाडु से 15 स्टूडेंट्स गए हैं।

मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सुधार जरूरी

पूर्व भारतीय एंबेसडर और डायरेक्टर गेटवे हाउस नीलम देव ने कहा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितयों में काफी परिवर्तन आ रहा है। आज हम जी 20 जैसे समूह में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अब भी हमें सुधार करना होगा, ताकि हम ग्लोबल लेवल पर नीतियों को प्रभावित कर सकें अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें। देव ने कहा अभी भी आईएमएफ, विश्व बैंक में अभी भी भारत का वोट शेयर बहुत कम है। विश्व के राजनीतिक संस्थानों में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जहां भारत के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की आलोचना की जाती है वहीं विकसित देश अपने यहां कृषि पर सब्सिडी दे रहे हैं। हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के लिए मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सुधार करना होंगे। कम लागत में अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, तभी दूसरे देशों से बराबरी कर पाएंगे।

Naidunia, July 8, 2018 Page-19

शहर आए बॉलीवुड अभिनेता राजा बुंदेला से नईदुनिया की खास चर्चा

यदि सरकार फिल्म पॉलिसी लाए तो मप्र बन सकता है फिल्म मेकिंग हब

इंदौर। नईदुनिया रिपोर्टर

मध्यप्रदेश में फिल्म मेकिंग हब बनने की अपार संभावना है। यहां कई लोकेशंस पर बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो रही है। यह सांस्कृतिक रूप से विकसित राज्य है, लेकिन अभी यहां स्थानीय फिल्ममेकर्स सामने नहीं आ पा रहे। इसके लिए सरकार को फिल्म पॉलिसी लाना होगी। जिस तरह महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और झारखंड में है, उसी तरह यहां भी फिल्मों पर सब्सिडी का प्रावधान हो। बड़े सिनेमा हॉल में बड़ी फिल्मों के साथ स्थानीय फिल्में भी लगाना चाहिए, तभी लोग इनमें आएंगे।

यह बात अभिनेता राजा बुंदेला ने गुरुवार को नईदुनिया से खास चर्चा में कही। बुंदेला 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को समझाओ' कार्यक्रम में हिस्सा लेने

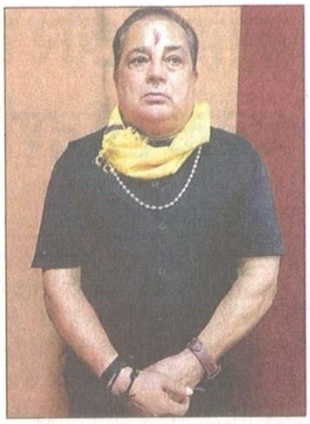

शहर आए थे। बुंदेला कहते हैं कि कई देशों में हिंदी फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं, लेकिन हमें इनके साथ कम बजट की रियलिस्टिक पेरेलल सिनेमा को भी बढ़ावा देना होगा।

फिल्मों की क्वालिटी की जगह ध्यान कमाई पर

मैं फिल्मों के व्यवसायीकरण के विरोध में नहीं हूं, लेकिन आज अजीब होड़ लगी हुई है। पहले लोग एक फिल्म से बेहतर दूसरी फिल्म बनाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज यह देखा जाता है किसने कितना व्यापार किया। अगर एक अभिनेता को 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो दूसरा 3 करोड़ कैसे मिले बस इसके पीछे लगा है। पहले हर फिल्म कुछ मैसेज देती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। गुरुदत्त, राजकपूर, सत्यजीत रे कुछ ऐसे नाम हैं, जिनकी हर फिल्म में मैसेज होता था। आज फिल्म निर्माता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वे इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। सच तो यह है कि फिल्म बनाने के पहले पूरी जानकारी हासिल करना चाहिए, क्योंकि एक खराब फिल्म से न सिर्फ दर्शक, बल्कि फिल्म बनाने वाले और फिल्म में काम करने वालों को भी नुकसान पहुंचता है।

आईआईएम के स्टूडेंट्स की मूवी ने जीता प्रथम पुरस्कार

'मम्मी तेरी लाड़ली को बहुरूपिए ले गए। बचपन और मासूमियत को उजाड़ ले गए।' बचपन में हर बच्चे ने 'नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए' गीत जरूर सुना है, उसी के शब्दों को परिवर्तित कर बनाई गई डेढ़ मिनट की शॉर्ट फिल्म 'यट अनादर सेव गर्ल' ने प्रथम पुरस्कार जीता। भारतीय प्रबंध संस्थान के आईपीएम प्रोग्राम के सेकंड ईयर के प्रत्यक्ष दुबे और उनकी टीम ने इस दिल को छू जाने वाले गीत के माध्यम से बताया कि हमारे समाज में बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। दूसरा पुरस्कार फिल्म 'लाइफ इन मोशन' और तीसरा 'आरवी' को मिला। कार्यक्रम में कुल 9 फिल्में प्रदर्शित की गई थीं।

थेलेसेमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 'मां-बेटी सबसे अच्छी' प्रतियोगिता रखी गई। जिसमें मां और बेटी को एक जैसे परिधान पहनना थे। इसकी विजेता वंदना मेहता और उनकी बेटी निषिका मेहता रहीं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसे समझाओ' मुहिम के प्रदेश संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि आज के सभ्य समाज में भी रावण और दुर्योधन जिंदा हैं। सभी को एकजुट होकर इन्हें खत्म करना होगा। डॉ.रजनी भंडारी ने कहा बेटियों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाने से ज्यादा उनका सही क्रियान्वयन जरूरी हैं, इसमें पुलिस और वकील की भूमिका महत्वपूर्ण है।

Naidunia, (Our City) July 6, 2018 Page-16

'Trump's trade policies are harming the world economy'

TIMES NEWS NETWORK

Indore: United States president Donald Trump's policies on international trade and multilateral agreements have disrupted global supply chain that has impact on all economies of the world, said former ambassador Neelam Deo on Saturday.

"Disruption has affected all economies but India has hedged to disturbances by building close relationship with western countries, joint military exercises and weapon purchases," said Deo, on the sidelines of IIM Indore's industry meet.

Deo, who served as Indian ambassador to Denmark and other countries, said high quality of professional services, skilled labour will aid India to cater to new demand emerging from the world.

Referring to India's poor export performance, she said that here manufacturing needs to be upgraded and infrastructure should be improved.

"We have trade deficit

IIM INDUSTRY MEET

with almost all countries and exports have been poor year on year which means that manufacturing need to be enhanced and a proper infrastructure needs to be established."

Former ambassador stressed that India needs to initiate exports of generic medicines to China.

"The fact that exports are not good shows that you are not competitive. Among the region we are not competitive because infrastructure is poor and ports are not as efficient as in other countries," said Deo.

Speaking on new tax regime Goods and Services Tax (GST), she said with GST at least India will get a unified tax structure up to a point but like India no other country has five slabs.

Answering a question on India-China relation, the former ambassador said, this government has decided to improve its relationship with China and has moved in that

Pravin Barnale

Delegates at IIM-Indore's industry meet on Saturday

Japanese keen on investing in agri, automobile sector

TIMES NEWS NETWORK

Indore: India has become a potential investment ground for Japanese with investment worth crores of rupees likely to be pumped into the system in coming years if a proper ecosystem is established, said a consultant to Japanese investors on Saturday.

"There is huge potential in India for Japanese investments especially in sector of agriculture and electronic vehicles but lack of infrastructure is a barrier," Tomio Isogai, a freelance advisor in Indo-Japanese relations based out of Pune, said on the sidelines of IIM-Indore's industry meet.

Isogai said India needs to develop an industrial supportive infrastructure and a single window mechanism to expedite the policy matters.

He said proposed roll out of Japan backed Mumbai-Ahmedabad bullet train scheduled to be ready by 2022 is likely to miss the deadline due to procedural delays demoralizing investors.

Madhya Pradesh government is also banking on Japanese investments in its ambitious Smart Industrial Park where a separate Japanese township has been earmarked to attract automobile manufacturers.

> "There is huge potential in India for Japanese investments especially in sector of agriculture and electronic vehicles but lack of infrastructure is a barrier. "India should work on bridging the gap and enhance its productivity and limit food wastage
>
> **Tomio Isogai**

Isogai said, Japanese are mainly looking to explore areas of agriculture and automobile in India as expertise and technology of Japan can be utilized to enhance the market.

"India should work on bridging the gap and enhance its productivity and limit food wastage," said Isogai.

He explained that by 2030, countries like India will have a higher share of younger population than Japan and latter could use the skill of Indian population to its advantage via a strategic business partnership with the country.

Isogai said the delay in the implementation of the policies in India hurts investments coming to the country.

Experts lay emphasis on industry infra development

Indore: India's manpower must be skill-ready and best infrastructure should be put in place to take advantage of impending upturn in the economy in coming years, eminent speakers said on Saturday.

Experts from distinguished fields shared their views and experience with students and industry players at a lecture series organised by Indian Institute of Management (IIM), Indore in collaboration with Ministry of External Affairs.

National Skill Development Corporation MD Manish Kumar said, "Focus is now to improve quality of skill education and training to bridge the gap between demand and supply."

He emphasised on importance of skill development in country especially in bringing members of insurgent groups back to mainstream.

He talked about how between 90s and now, India entered the growth phase and how the growth is only going to increase over next few years.

The institute also conducted annual Industry Meet on theme —The 3Ist: Industry, Innovation and Infrastructure for India's Economic Growth.

"IIM Indore's connect with industry has grown tremendously over the years. Every year, we send 500 students to different industries for completing projects and understand practical requirements," said Rajendra Jain, an industrialists and a committee member at Industry Interface Office, IIM.

Industry Interface Programme (IIP) run by IIM-I facilitates students to complete live projects under mentorship of industry partners and faculty.

Professor Abhishek Mishra lauded students for their efforts in live projects this year with more than 99 per cent groups either meeting or exceeding expectations.